International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 7.328
Vol.9 No.2 Nov – Dec 2021

अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों का एक अध्ययन

Poonam Chand Gupta1 Dr. Jainendra Patel[2]
[1]Research Schoolar, Law, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
[2]Associate Professor, Dept. of Law, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)

सार :–
भारत की स्वदेशी जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है और उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए एक स्पष्ट आह्वान देश के भीतर लंबे समय से गूंज रहा है। आदिवासियों के लिए सामाजिक न्याय की चिंता के रूप में भूमि की भारत भर में विद्रोहों और संघर्षों में एक लंबी ऐतिहासिक मिसाल है। भूमि अधिकारों का दावा विशिष्ट पहचान और संसाधनों के भौतिक पुनर्वितरण दोनों की मांग है। यह पेपर आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनके संवैधानिक अधिकारों की जांच करता है। और उस कानून का विश्लेषण करता है जो उन्हें भूमि अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा यह पेपर कानून की कमियों को स्पष्ट करता है और निष्कर्ष और सुझावों के साथ समाप्त होता है। आदिवासियों को भूमि अधिकारों की गारंटी देने वाले मजबूत कानून कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें आधे–अधूरे मन से लागू किया गया है और फिर भी राज्यों और यहां तक कि राज्यों में क्षेत्रों के बीच बहुत भिन्नता के साथ लागू किया गया है।

प्रस्तावना :–
आदिवासी शब्द 1930 के दशक में भारत के विभिन्न स्वदेशी लोगों के बीच पहचान की भावना पैदा करने के लिए गढ़ा गया था। आदिवासी एक सजातीय समूह नहीं हैं और जातीयता और संस्कृति में बहुत भिन्न हैं और अलग–अलग बोलियों के साथ सौ से अधिक भाषाएं भी बोलते हैं। उनके जीवन के तरीके में समानताएं हैं और आमतौर पर उन्हें समाज के उत्पीड़ित वर्गों का हिस्सा माना जाता है। 2011 में हुई आधिकारिक जनगणना से पता चलता है कि आदिवासी देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है जो लगभग 104 मिलियन लोग हैं। अनौपचारिक आंकड़े महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं लेकिन भारत की जनसंख्या के बहुत अधिक अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश आदिवासी देश के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके व्यवसाय में मुख्य रूप से खेती, मछली पकड़ना और वन उपज एकत्र करना शामिल है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
आदिवासी या स्वदेशी लोग उन लोगों के वंशज हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय से रहते थे जब विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के लोग आए थे। 2000–1500 ईसा पूर्व आर्यों के आगमन से बहुत पहले भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न आदिवासी समुदायों का घर रहा है। आर्य और आदिवासी समुदायों के पास अलग–अलग पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थान हैं। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों ने आदिवासियों का वर्णन करने के लिए ''असुर'' शब्द का इस्तेमाल किया और उन्हें आर्यों के अधीन होने के लिए चित्रित किया गया। आदिवासियों को मुख्यधारा के हिंदू जाति समाज में एकीकृत नहीं किया गया था लेकिन संपर्क के कई बिंदु थे। स्वदेशी धार्मिक में हिंदू धर्म के कई पहलू शामिल थे और इसके विपरीत। आर्यों के बसने और दो समुदायों के निकट संपर्क के कारण पैदा हुए संघर्षों ने आदिवासियों को जीवित रहने के लिए जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर धकेल दिया। पूरे इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप ने कई आक्रमण देखे, यह स्वदेशी समुदाय था जो इस तरह के आक्रमणों का खामियाजा भुगतता रहा और अधिक बार नहीं, प्रमुख समाज को कुछ आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। नृविज्ञान ने आदिवासियों को आदिम, जंगली, असभ्य और जंगली के रूप में परिभाषित और वर्णित किया।

भूमि अधिकार, संविधान के तहत

1950 के संविधान के तहत आदिवासी तथाकथित अछूतों के साथ विशेष सुरक्षात्मक प्रावधानों के अधीन हो गए। स्वदेशी लोगों के विशाल बहुमत को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अनुच्छेद 341 भारत के राष्ट्रपति को जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत पांचवीं और छठी अनुसूचियों में निर्दिष्ट आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन का प्रावधान था। पांचवीं अनुसूची भारत के आठ राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्र कहे जाने वाले आदिवासी भूमि के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रदान करती है। पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी (आदिवासी) लोगों को उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से गैर–आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करती है। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के संबंध में राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। पांचवीं अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, राज्यपाल न केवल यह निर्देश दे सकते हैं कि कोई विशेष कानून या उसका हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, बल्कि वे ऐसे क्षेत्रों में सुशासन और शांति के लिए नियम भी बना सकते हैं। राज्यपाल 3 मनीष मीणा द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध या प्रतिबंध से संबंधित क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, आदिवासियों के विमुद्रीकरण और अपराधीकरण के पीछे ब्राह्मण और औपनिवेशिक इतिहास।

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बीच, ऐसे क्षेत्रों में भूमि आवंटन का विनियमन और धन उधार गतिविधियों का विनियमन, यह जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श से किया जाता है। औपनिवेशिक काल से ही भारतीय आदिवासियों के लिए भूमि अधिकारों का प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और कई अन्य स्थानों की तरह, भूमि स्वामित्व की अवधारणा यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन के साथ शुरू हुई। जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने देश भर में वानिकी का एक बड़ा उद्यम शुरू किया और वन भूमि की संपत्ति का विचार पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आदिवासियों के लिए भूमि के स्वामित्व का नुकसान हुआ। खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों ने 1832 से 1905 तक लगातार विद्रोहों को उकसाया है। जैसा कि पहले देखा गया है कि संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों से संबंधित है। पांचवीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है जो अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्र में शामिल हैं। इस प्रावधान के साथ महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल आठ राज्य शामिल हैं जिन्हें संविधान ने आधिकारिक तौर पर अनुसूचितश घोषित किया है और अब तक दस राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 5 हैं। इस प्रकार कई राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी को अनुसूचित क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो ऐसे राज्यों में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों पर सवाल उठाता है। संविधान की छठी अनुसूची उत्तर पूर्व की विशिष्ट जनजातियों को स्वायत्तता प्रदान करती है। छठी अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों पर लागू होती है। छठी अनुसूची जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद नामक स्वायत्त निकायों को कुछ शक्तियाँ प्रदान करती है और आदिवासी भूमि अधिकारों के संबंध में, इन निकायों को भूमि के आवंटन, व्यवसाय, उपयोग या अलग करने, वन के प्रबंधन पर कानून बनाने का अधिकार है। संपत्ति की विरासत और साहूकार के नियमन पर6.

अधिनियम के तहत, वन अधिकार

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे अन्यथा वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, संसद द्वारा 2006 में पारित किया गया था। कानून ने पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि तक पहुंच, प्रबंधन और शासन करने का अधिकार वापस दे दिया। और गांव की सीमाओं के भीतर संसाधन, जो औपनिवेशिक काल से वन विभाग द्वारा नियंत्रित किए गए थे। कानून ग्राम सभा को भी वैधानिक बनाता है

वन भूमि के प्रबंधन और उनकी रक्षा के लिए निकाय। यह प्रावधान करता है कि इन वनों में तब तक कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उन पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का निपटारा नहीं हो जाता। वन अधिकार अधिनियम में आदिवासियों के लिए भूमि अधिकारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की क्षमता है। वन अधिकार अधिनियम में आदिवासियों और अन्य वनवासियों दोनों के लिए कई मौलिक प्रावधान शामिल हैं जो यह साबित

कर सकते हैं कि वे 2005 की कट ऑफ तिथि से पहले वन भूमि पर निवास करते थे और इसमें खेती और घर दोनों के अधिकार, गैर–लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार और सामुदायिक भूमि का कार्यकाल। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की प्रस्तावना यह दर्शाती है कि वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों के खिलाफ उनके भूमि अधिकारों की बेदखली और गैर–मान्यता के संबंध में किए गए ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है। अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासी लोग अपने जंगल का प्रबंधन स्वयं करें जो अधिकारियों द्वारा वन संसाधनों के दोहन, वन शासन और प्रबंधन के साथ–साथ आदिवासी अधिकारों आदि को नियंत्रित करेगा।

वन अधिकार अधिनियम की कमी

वन अधिकार अधिनियम में निश्चित रूप से आदिवासियों को भूमि अधिकार देने से संबंधित प्रशंसनीय प्रावधान हैं जो लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अधिनियम के कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख कमियां हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन और सामुदायिक भूमि अधिकारों की मान्यता केवल कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात में पर्याप्त रूप से हुई है। अन्य राज्यों और क्षेत्रों में वन नौकरशाही में शक्तिशाली निहित स्वार्थों के विरोध द्वारा और विशेष रूप से इसके कट्टरपंथी सामुदायिक प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को बाधित और बाधित किया गया है। उदाहरण के लिए ग्रामीण उत्तर प्रदेश में, वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा संगठित भूमिहीन आदिवासियों और दलित मजदूरों के एक समुदाय ने वन भूमि पर कब्जा करने और रामनगर नामक अपना गाँव स्थापित करने का फैसला किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य काम के लिए यादव जमींदारों पर उनकी निर्भरता को समाप्त करना था और वन अधिकार अधिनियम के निर्माण ने आदिवासियों में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की थी। महिला मजदूर किसान संगठन (एमएमकेएस) ने वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को वन भूमि पर अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए मार्शल किया और उन्होंने 2005 की कट–ऑफ तिथि से पहले भूमि पर कब्जा करने का दावा किया, जो भूमि के स्वामित्व के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। भूमि पर कब्जे को स्थानीय कुलीनों से पर्याप्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और यादव समुदाय के लोगों के नेतृत्व में भीड़ के हमले में रामनगर को अंततः जमीन पर गिरा दिया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रामनगर को बड़े पैमाने पर संभव बनाया गया था

छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम संभावित रूप से लगभग 7.4 मिलियन आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भूमि अधिकारों का दावा करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, इनमें से आधे दावों को खारिज कर दिया गया है और जमीन को अक्सर मनमाने ढंग से छीन लिया गया है। गोंड जनजाति के एक आदिवासी सुंदर सिंह कुमेती की जंगल में जमीन के एक हिस्से तक पहुंच नहीं रही, जिसे उन्होंने और उनके परिवार ने दो पीढ़ियों से चरा रखा था। 2016 में एक रेलवे परियोजना के हिस्से के रूप में एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जंगल के सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण के उद्देश्य से श्रमिकों ने लगभग 300 साल, साजा और फलों के पेड़ काटे। अगले वर्ष, भारी मशीनरी को तैनात किया गया और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया। विनाश के बाद एक एकड़ भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई और कुमेती को नहीं पता कि उसने कितनी जमीन खो दी। कुमेती भाग्यशाली हैं कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से उनके पास सहारा के लिए एक ऐतिहासिक कानून है, जिसे आदिवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए बनाया गया था। भारत में कई हज़ार अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों के लिए, वन अधिकार अधिनियम या थ्र।, लैमिनेटेड पेपर की एक शीट है। पट्टा या टाइटल डीड, जो मालिकों द्वारा बारीकी से संरक्षित है, अक्सर उनका सबसे मूल्यवान अधिकार होता है, जो उनकी वन भूमि के अधिकारों के लिए उनके अधिकार को साबित करता है। एफआरए के प्रावधानों के अनुसार, वनवासियों के पास व्यक्तिगत अधिकार हैं और ग्रामीणों के पास भूमि के उन हिस्सों पर सामुदायिक अधिकार हैं जिन्हें उन्हें उचित तरीके से प्रबंधित करने की अनुमति है। गैर–वन उद्देश्यों के लिए भूमि के किसी भी हस्तांतरण के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। कुमेती के पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि वह 2.5 एकड़ की वन भूमि के मालिक हैं। हालांकि उनकी जमीन का एक हिस्सा रेलवे परियोजना के लिए ले लिया गया था। कुमेती और अन्य ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि के उन हिस्सों को इंगित करने के प्रयास जो अब दुर्गम हो गए हैं, भारी सशस्त्र गश्ती दल द्वारा विफल किए जा रहे हैं।

अन्य आदिवासी ग्रामीणों को भी इसी तरह के अनुभव हुए हैं जहां अधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण के भूमि के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया है। ये उदाहरण नौकरशाही बाधाओं पर प्रकाश डालते हैं जो एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और उन्हें क्रियान्वित करने में उदासीनता को रोकते हैं।

लैंडमार्क निर्णय, समथा मामले में

आदिवासी आंध्र प्रदेश में भूमि संबंधों का इतिहास, साथ ही साथ शेष जनजातीय मध्य भारत में, कृषि भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ आवर्ती संघर्षों में से एक है। गैर–आदिवासी किसानों और साहूकारों के लिए घाटियाँ, और पहाड़ियों पर और उसके आसपास वन भूमि के स्वामित्व के सरकार के दावे के खिलाफ। राज्य सरकारों द्वारा घाटियों में कृषि भूमि पर आदिवासी कानूनी अधिकारों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने वन भूमि पर नियंत्रण बनाए रखा है, जिससे कई आदिवासी पीढ़ियों से असुरक्षित हैं। एफआरए ने वनवासी समुदायों के पक्ष में बदलाव की कुछ आशा प्रदान की। फिर भी बांध और खदानों सहित विकास परियोजनाओं द्वारा बेदखली की धमकियों ने अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रयासों को विफल कर दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, आदिवासियों से संबंधित भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए कानून क्रमिक रूप से पारित किया गया था, जिसकी परिणति आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन 1959 के निर्माण में हुई, जिसे भूमि हस्तांतरण विनियमन भी कहा जाता है। भूमि हस्तांतरण विनियमन जैसा कि वर्तमान में है, किसी को भी किसी भी प्रकार की भूमि के हस्तांतरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, लेकिन एक आदिवासी व्यक्ति या एक पंजीकृत आदिवासी सहकारी समिति। इसमें महत्वपूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व वाली वन भूमि शामिल है। कानून यह भी मानता है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में सभी भूमि मूल रूप से एक आदिवासी व्यक्ति की थी, जिसका अर्थ है कि एक गैर–आदिवासी मालिक के कब्जे में पाई गई भूमि को मूल भूमि को वापस किया जाना चाहिए।

आने वाली चुनौतियां

एफआरए के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक उदासीनता सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा जारी है और कई बार उनके जमीन के दावे को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया है. दूसरे, न केवल आदिवासियों में बल्कि नौकरशाही के स्तर पर जागरूकता की कमी भयावह रही है। वन अधिकारों के दावों को संसाधित करने में मदद करने वाले वन अधिकारियों के निचले स्तर पर अनभिज्ञता अधिक है और इससे दावों के समाधान में विसंगतियां पैदा हुई हैं। वन नौकरशाही ने आदिवासियों के लिए कल्याणकारी उपाय के बजाय अतिक्रमण को नियमित करने के लिए एक साधन के रूप में एफआरए की गलत व्याख्या की है। अधिनियम का कमजोर होना बहुत चिंता का विषय है क्योंकि राज्यों में ग्राम सभाओं को वन अधिकार देने में भिन्नता है जो स्थानीय लोगों को वन संसाधनों पर नियंत्रण देता है जो राज्यों द्वारा एकत्र किए गए वन राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए कुछ पर्यावरणविद इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि कुछ राज्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों को वरीयता देने और अधिनियम में निहित सामुदायिक अधिकारों को दबाने के लिए एफआरए अधिनियम को कमजोर कर दिया है। अंत में, वन नौकरशाही की ओर से पालन करने की अनिच्छा अधिनियम के इस डर से कि यह वन भूमि पर अपनी भारी शक्ति खो सकता है, ने भी एफआरए के सभी दोषपूर्ण कार्यान्वयन में जिम्मेदार ठहराया है। न्यायिक फैसलों ने आदिवासियों के कर्ज में भी इजाफा किया है और उन्हें सरकार और न्यायपालिका से उम्मीद खोने के कगार पर धकेल दिया है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में एफआरए के कार्यान्वयन पर अपने फैसले में, दो मिलियन से अधिक आदिवासियों के जीवन को खतरे में डाल दिया, जो इस फैसले के कारण अपनी जमीन और घरों से बेदखल होने के कगार पर थे। अदालत ने लगभग दो दर्जन राज्यों के अधिकारियों को एफआरए के तहत निपटाए गए दावों का विवरण प्रस्तुत करने और 24 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के आवेदन ठुकरा दिए थे, उन्हें बेदखल करने के लिए कहा। कड़े विरोध और प्रतिक्रिया के बाद, अदालत ने बाद में आदिवासियों को अस्थायी राहत प्रदान की।

निष्कर्ष

भूमि अधिकारों का क्षेत्र भारत में आदिवासी समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण और दबाव वाली चिंताओं में से एक रहा है। आदिवासियों के लिए भूमि अधिकार सुरक्षित करने से सरकार को लंबे समय से उत्पीड़ित समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का अवसर मिलता है, लेकिन इसके लिए आधा–अधूरा प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने और इस तरह उन्हें वंचित करने में विकास परियोजनाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है एक आजीविका का। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासियों के प्रति यह उदासीन रवैया जारी न रहे, सरकार को अपने विकास के एजेंडे और आदिवासियों के अधिकारों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा। सरकार आदिवासियों के लिए भूमि अधिकार हासिल करने के अपने इरादे पर खरी उतरेगी यदि वह एक बार में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी को उनकी भूमि से विस्थापित करने में सक्षम बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को रोक देती है। विकास और आधुनिकीकरण की कीमत पर आदिवासी भूमि को बेदखल करना और उनके अधिकारों को छीनना ही उन्हें और भी अलग–थलग कर देगा और असमान विकास का एक झकझोर देने वाला उदाहरण होगा। वन अधिकार अधिनियम एक स्वागत योग्य कानून था जिसने आदिवासियों को उन वन भूमि तक पहुँचने और प्रबंधन करने का अधिकार दिया जो औपनिवेशिक काल से वन अधिकारियों के नियंत्रण में थी। लेकिन नौकरशाही की उदासीनता अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में एक बाधा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासियों के भूमि दावों को सुना जाए और ठीक से संसाधित किया जाए, नौकरशाही में खामियों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। अंततरू वन अधिकार अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा ग्राम सभा को उनके गुप्त उद्देश्यों के लिए दी गई शक्तियों को हथियाने के प्रयास में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

- अद्वैत राज, (2020) कानून प्रबंधन और मानविकी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, आई.एस.एस.एन. 2581–5369, खंड 3 द्य अंक 4
- पांचवीं अनुसूची क्षेत्र, ीजजचेरू/ /अपोंचमकपं.पद/वबपंस – ूमसतिम/बीमकनसमक – जतपइमे – ूमसतिम/पिजी –`बीमकनसम – ंतमें।
- ूकतपीजपपें.बवउ।
- पांचवीं अनुसूची क्षेत्र, ीजजचेरू/ /अपोंचमकपं.पद/वबपंस – ूमसतिम/बीमकनसमक – जतपइमे – ूमसतिम/पिजी –`बीमकनसम – ंतमें।
- ीजजचेरू/ /ूकतपीजपपें.बवउ।
- अल्फ गुनवाल्ड निल्सन, आदिवासी और राज्य भारत के भील हार्टलैंड में सबाल्टर्निटी एंड सिटीजनशिप 257–258 (2018)।
- जैकब कुशी, एलियंस अपनी ही भूमि मेंरू जब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को अतिक्रमणकारियों में बदल दिया गया, द हिंदू, 06 अप्रैल, 2019।